



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 2019/माघ 23, 1940

No. 61]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 2019/MAGHA 23, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 30 जनवरी, 2019

सं. टीएएमपी/66/2018-केओपीटी।—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त हल्दिया डॉक परिसर (एचडीसी) में पाइपों द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन मानक आधार पर दंड/प्रोत्साहन की वैधता के विस्तार के प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/66/2018-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी, 2019 के 18वें दिन पारित)

मामला कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त हल्दिया डॉक परिसर (एचडीसी) में पाइपों द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन मानक आधार पर दंड/प्रोत्साहन की वैधता के विस्तार के प्रस्ताव संबंधित है।

2.1. यह स्मरण कराया जाता है कि खाद्य तेल पोत की पम्पिंग दर में वृद्धि लाने और टर्न-अरांउ समय (टीआरटी) को घटाने के उद्देश्य से, केओपीटी जुलाई 2017 में एक प्रस्ताव लाया कि एचडीसी पर पाइपलाइनों द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के

लिए निष्पादन आधार पर दंड/प्रोत्साहन से संबंधी एक उपबंध अंतर्विष्ट किया जाये। विधिवृत् परामर्शी प्रक्रिया के पश्चात् इस प्राधिकरण ने 14 नवंबर, 2017 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/59/2017-केओपीटी के द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन आधारित प्रोत्साहन/दंड का अनुमोदन किया। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 29 नवंबर, 2017 को राजपत्र संख्या 447 में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश के उपबंध 1 अगस्त 2017 से 31 जुलाई 2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य थे।

2.2. इसके अतिरिक्त, जैसा केओपीटी ने स्वीकार किया था, केओपीटी को 14 नवंबर, 2017 के उक्त आदेश के पैरा 8.4 में सलाह दी गई थी कि वह क्रूड पॉम तेल/आरबीडी पॉम तेल की डुलाई करने वाले पोतों के लिए 250 एमटी प्रति घंटा और क्रूड सोयाबीन/सूरजमुखी तेल की डुलाई करने वाले पोतों के लिए 450 एमटी प्रति घंटा की न्यूनतम पंसिंग दर की समीक्षा करे और 31 जुलाई 2018 से आगे इस अवधि को बढ़ाने के लिए इन उपबंधों की समाप्ति से कम से कम 2 महीना पहले एक उपयुक्त प्रस्ताव दायर करे।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, केओपीटी ने अपने 30 अगस्त, 2018 के पत्र संख्या एमटीओ/जी/19-बी/भाग.1/जीएमटी-476 के द्वारा एचडीसी पर पाइपलाइनों द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन आधार पर दंड/प्रोत्साहन नवंबर 2017 के आदेश में यथा अनुमोदित, की वैधता के विस्तार का प्रस्ताव दायर किया। केओपीटी द्वारा किये गए मुख्य निवेदन इस प्रकार हैं:

- (i). खाद्य तेल पोतों के निष्पादन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ एचडीसी पर खाद्य तेल कार्गो की प्रमाण में वृद्धि लाने के लिए केओपीटी के न्यासी मंडल ने 31.05.2017 को संकल्प संख्या आर/279/एचडीसी/एसएचएंडसीएच/315/2017 के द्वारा 01.08.2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए एचडीसी पर पाइपों के माध्यम से खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन आधारित दंड/प्रोत्साहन मानकों को अनुमोदित किया और तत्पश्चात् इसकी समीक्षा की जायेगी। उक्त मानक 29.11.2017 के राजपत्र संख्या 447 में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किये गए।
- (ii). मानकों के लागू होने के साथ, केओपीटी ने खाद्य तेल पोतों में निष्पादन में सुधार के साथ-साथ कार्गो की मात्रा में वृद्धि भी पाई जो निम्नवत् है:

अवधि	प्रहस्तित टन भार	क्रूड पॉम तेल की औसत उत्पादकता (एमटी/घंटा)	सोयाबीन तेल की औसत उत्पादकता (एमटी/घंटा)
1.8.2016 से 31.7.2017 *	2.37 एमएमटी	160.58	286.87
1.8.2017 से 31.7.2018 **	2.40 एमएमटी	202.21	295.38
% variation	1.35	25.92	2.61

*निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड के कार्यान्वयन से पहले की अवधि।

**निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड के कार्यान्वयन से बाद की अवधि।

- (iii). चूंकि एचडीसी में खाद्य तेल यातायात में और वृद्धि की काफी गुंजाइश है, केओपीटी के न्यासी मंडल ने 28.06.2018 के अपने संकल्प संख्या आर/81/एचडीसी/एसएचएंडसीएच/3/06/2018 के द्वारा एचडीसी पर पाइपलाईनों द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन आधार पर दंड/प्रोत्साहन को उन्हीं निवंधनों और शर्तों पर 01.08.2018 से एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। केओपीटी द्वारा बोर्ड के संकल्प की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3.2. तदनुसार, केओपीटी ने एचडीसी में पाइपलाइनों के द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन मानक आधारित दंड अथवा प्रोत्साहन को 01 अगस्त, 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाने का अनुमोदन चाहा है।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार केओपीटी के 30 अगस्त, 2018 के प्रस्ताव की एक प्रति हमारे 6 सितंबर, 2018 के पत्र के साथ प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गई। इसके जवाब में, कुछ प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। उक्त टिप्पणियों को फीडबैक सूचना के रूप में केओपीटी को भेजा गया था। केओपीटी ने अपने 20 सितंबर, 2018 के पत्र के द्वारा उन पर अपना उत्तर दिया।

5. संदर्भाधीन मामले में केओपीटी परिसर में 1 नवंबर, 2018 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में, केओपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाईट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुनवाई में केओपीटी और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों द्वारा अपने निवेदन रखे।

6. केओपीटी को हमारे 12 नवंबर, 2018 के पत्र के द्वारा कुछ सूचना/स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया। केओपीटी ने 21 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र के द्वारा उत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उस पर केओपीटी के उत्तर को नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	केओपीटी का उत्तर
(i).	खाद्य तेल प्रहस्तन से संबंधित निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड के क्रियान्वयन से केओपीटी ने कितना प्रोत्साहन दिया या कितना दंड प्राप्त हुआ।	स्क्रीम के लागू होने पर 01.08.2017 से 30.11.2018 तक 68,310/- रु. केओपीटी द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दिये गए तथा उसी अवधि में केओपीटी को 2,81,33,615/- रु. दंड के रूप में प्राप्त हुए।
(ii).	केओपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन और दंड का आधार प्रस्तुत किया जाए।	पाइपलाइन के द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ दांडिक मानकों का प्रस्ताव पोत परिवहन मंत्रालय को 16.06.2016 के प9 संख्या पीडी-11033/73/2013-भाग के द्वारा परिचालित महापतन शुक्र बल्क कार्गो बर्थिंग नीति दिशानिर्देश 2016 के प्रत्युत्तर में प्रस्तावित किये गए। उक्त बर्थिंग नीति में प्रोत्साहन के साथ-साथ दंड को निष्पादन मानकों के साथ संबद्ध किया गया है। प्रोत्साहन/हतोत्साहन संबद्ध निष्पादन मानकों का उद्देश्य सभी पत्तनों/ग्राहकों के उत्पादकता मानकों में निरंतर सुधार लाना है। इस प्रकार पत्तन की महता को बढ़ाने के साथ-साथ ग्राहकों और व्यापार के संभरण की लागत को कम करना है। उक्त सिद्धांत एचडीसी पर तरल कार्गो प्रहस्तन के लिए प्रोत्साहन/दंड मानक निर्धारित करने के लिए अपनाया गया है।
(iii).	इसके अतिरिक्त, संयुक्त सुनवाई के दौरान, केओपीटी ने सूचित किया कि इसने और प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकता है। क्या कोई गुंजाइश उपलब्ध है। तदनुसार, एचडीसी इस पहलु पर उक्त के संदर्भ में परीक्षण करे और यदि आवश्यक हो तो अपना प्रस्ताव संशोधित करे।	उच्च प्रोत्साहन के बारे में यह बताया जाता है कि 01.08.2016 से 31.07.2017 तक और साथ ही 01.08.2017 से 31.07.2018 तक प्रहस्तित पोतों में से अधिकतर ने निष्पादन मानक प्राप्त ही नहीं किया। इसलिए, इस समय उच्च प्रोत्साहन देने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

7. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

8. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:

- (i). खाद्य तेल पोतों के टर्न-अराउंड समय (टीआरटी) में सुधार लाने को ध्यान में रखकर और तदनुसार वर्थ के क्षमता उपयोग में वृद्धि लाने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) हल्दिया गोदी परिसर (एचडीसी) में पाइपलाइन के द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड के अनुमोदन का प्रस्ताव के साथ आया था। तदनुसार, इस प्राधिकरण ने 14 नवंबर, 2017 के आदेश संख्या एएमपी/59/2017-केओपीटी के द्वारा एचडीसी पर खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन मानक आधार पर प्रोत्साहन/दंड का अनुमोदन किया था। उस आदेश के अनुसार, क्रूड पॉम तेल/आरबीडी पॉम तेल की दुलाई करने वाले पोतों के लिए 250 एमटी प्रति घंटा और क्रूड सोयाबीन/सूरजमुखी तेल की दुलाई करने वाले पोतों के लिए 450 एमटी प्रति घंटा की न्यूनतम पंसिंग दर 01 अगस्त, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक एक वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी। इस पृष्ठभूमि में, केओपीटी एचडीसी पर पाइपों द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन आधार पर दंड/प्रोत्साहन नवंबर 2017 के आदेश में यथा अनुमोदित, की वैधता के विस्तार का एक वर्ष के लिए 01 अगस्त, 2018 से 31 जुलाई 2019 तक विस्तार के प्रस्ताव के साथ आया। केओपीटी के प्रस्ताव को केओपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।
- (ii). केओपीटी ने अपने 30 अगस्त, 2018 के अपने प्रस्ताव में किये गए निवेदन और संदर्भाधीन मामले की प्रक्रिया के दौरान केओपीटी द्वारा दी गई सूचना/स्पष्टीकरण को इस विश्लेषण में विचार में लिया जाता है।
- (iii). उस मामले से संबंधित कार्रवाई के दौरान, जो नवंबर, 2017 के प्रशुल्क आदेश के रूप में परिणत हुआ, केओपीटी ने 01 अगस्त, 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहन/दंड के उपबंध के साथ न्यूनतम पंसिंग दर के कार्यान्वयन का अनुमोदन चाहा था और तत्पश्चात् निष्पादन मानकों की समीक्षा करने की मंशा जाहिर की थी। खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड के कार्यान्वयन के साथ, पत्तन ने क्रूड पॉम तेल की औसत उत्पादकता में मात्र 25.92% वृद्धि और सोयाबीन तेल की औसत उत्पादकता में 2.61% की वृद्धि पायी गयी। पत्तन ने यह भी सूचित किया है कि अधिकतर पोतों ने निष्पादन मानक प्राप्त नहीं किये हैं। पत्तन द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार, इसने 01 अगस्त, 2017 से स्कीम के लागू होने की तारीख 30 नवंबर, 2018 तक मात्र 0.68 लाख रु. का प्रोत्साहन दिया है। और इसी अवधि के दौरान दंड के रूप में 281.34 लाख रु. की वसूली की है। इस स्थिति के आधार पर, पत्तन ने संदर्भाधीन प्रस्ताव में प्रचलित न्यूनतम पंसिंग दर को बढ़ाना उपयुक्त नहीं समझा गया और एचडीसी में खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड संबंधी विद्यमान उपबंधों को 01 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक 01 वर्ष के लिए विस्तार करने की वांछा प्रकट की है।
- (iv). (क). कुछेक प्रयोक्ताओं नामतः ईमासी बायोटेक लिमिटेड (ईबीएल), अदानी विलमार लिमिटेड (एडब्ल्यूएल), जेवीएल ऑयल रिफाइनरी (जेवीएलओआर) रूचि सोया इंडस्ट्रीय लिमिटेड (आरएसआईएल) और रूचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) ने निवेदन किया है कि निहित पिंसिंग प्रचालनों की संख्या को देखते हुए, वास्तविक औसत डिस्वार्ड दर क्रूड पॉम तेल/आरबीडी पॉम तेल के लिए प्रति घंटा 180 एमटी प्राप्त हुई है और क्रूड सूरजमुखी तेल/क्रूड सोयाबीन तेल की 280 एमटी प्रति घंटा निकलती है न कि क्रूड पॉम तेल/आरबीडी पॉम तेल दुलाई करने वाले पोतों के लिए 250 एमटी प्रति घंटा और क्रूड सोयाबीन/सूरजमुखी तेल की दुलाई करने वाले जहाजों की 450 एमटी प्रति घंटा और चूंकि पोतों द्वारा न्यूनतम पंसिंग दर प्राप्त नहीं की जा रही है इसलिए पोतों को भारी दंड प्रभार देन पड़ रहे हैं।

- (ख). न्यूनतम पंपिंग दर कूड़ पॉम तेल/आरबीडी पॉम तेल ढुलाई करने वाले पोतों के लिए 250 एमटी प्रति घंटा और कूड़ सोयाबीन/सूरजमुखी तेल की ढुलाई करने वाले जहाजों की 450 एमटी प्रति घंटा केओपीटी द्वारा तब यथा प्रस्तावित और नवंबर, 2017 के आदेश में अनुमोदित, एचडीसी पर कुछेक पोतों द्वारा वास्तविक औसत उत्पादकता प्राप्त/लगभग प्राप्त के आधार पर, जैसा उस समय एचडीसी ने सूचित किया था, निर्धारित की गई थी। इसे तब संबंधित हितधारकों के साथ हुई केओपीटी द्वारा आयोजित पत्तन स्तरीय बैठक के आधार पर भी पाया गया था।
- (ग). केओपीटी के अनुसार तब और साथ ही साथ अब भी कि यदि आयातकों/निर्यातकों और पोतों द्वारा डिस्चार्ज प्रचालन के दौरान विद्यमान प्रचालन संबंधी कमियां/बाधाएं पायी जायेंगी तो आयातकों तथा उनके प्रहस्तन एंजेटों द्वारा अतिरिक्त कम्प्रैशर, बूस्टर्स, बढ़िया पम्प और पर्याप्त पम्पिंग क्षमता के बढ़िया गुणता वाले पोतों की को लगाकर उन्हें ठीक किया जायेगा और उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी तो औसत उत्पादकता अधिक संघया में पोतों द्वारा सहजता से प्राप्त कर ली जायेगी।
- (v). केओपीटी द्वारा किये गए निवेदनों और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पत्तन के प्रस्ताव को उसके न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है और कि निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड के निर्धारण से आयातकों और प्रहस्तन एंजेटों में अनुशासन की भावना जागृत करेगा, यह प्राधिकरण न्यूनतम पम्पिंग दर के वर्तमान उपबंधों को प्रोत्साहन/दंड के उपबंधों के साथ 01 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने को प्रवृत्त है। पत्तन को सलाह दी जाती है कि वह 31 जुलाई, 2019 से आगे खाद्य तेल प्रहस्तन के निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसकी समीक्षा करें। संबंधित पत्तन प्रयोक्ताओं को भी सलाह दी जाती है कि वे तटीय अवसंरचनाओं को उन्नत करें, जैसा उन्होंने 04 मई 2017 और 18 जुलाई, 2017 को पत्तन द्वारा आयोजित बैठकों में सहमति जतायी थी।
- (vi). पत्तन ने यह प्रमाणित किया है कि 01 अगस्त 2017 से स्कीम के लागू होने से 30 नवंबर, 2018 तक की अवधि के 16 महीनों में 281.54 लाख रु. की राशि दंड के रूप में वसूली है। यदि निष्पादन मानकों की उपलब्धि/अनुपलब्धि की यह प्रवृत्ति बिना किसी परिवर्तन के जारी रहती है तो दिसंबर 2018 से जुलाई 2019 की अवधि के 8 महीनों में, यथानुपात आधार पर आया 141 लाख रु. निकलेगी। इस संबंध में, यह स्मरण किया जा सकता है कि नवंबर, 2016 में केओपीटी के सामान्य संशोधन आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा 383 करोड़ रु. तक का राजस्व घाटे को पत्तन द्वारा स्तर पर यथानुपात आधार पर से उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व को राजस्व घाटे में मिला दिया जाये और इससे केओपीटी का अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए।

9.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर खंड 21.6 - “निष्पादन के साथ-साथ एचडीसी पर पाइपों के द्वारा खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए उत्पादकता/प्रोत्साहन मानक” के अंतर्गत उप-खंड (ii) की वर्तमान टिप्पणी (iii) को निम्नलिखित टिप्पणी से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“(iii). निष्पादन और दंड/प्रोत्साहन मानक, ऊपर यथाविनिर्दिष्ट, 31 जुलाई 2018 की वैधता के साथ 1 अगस्त 2017 से प्रभावी को 01 अगस्त, 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया जाता है और 31 जुलाई 2019 तक यह वैध रहेंगे और उसके बाद इनकी समीक्षा की जायेगी।”

9.2. केओपीटी को दरमानों में उक्त उपबंध को अंतर्विष्ट करने की सलाह दी जाती है।

9.3. दिया गया अनुमोदन स्वतः ही व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इसके पश्चात इस प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से इसमें विस्तार नहीं कर दिया जाता। पत्तन को सलाह ही जाती है कि वह 31 जुलाई, 2019 से आगे विस्तार का प्रस्ताव दायर करते समय खाद्य तेल प्रहस्तन के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन/दंड की समीक्षा करे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन.-III/4/असा./536/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th January 2019

No. TAMP/66/2018-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Kolkata Port Trust seeking extension of validity for the performance norm based Penalty/ Incentive for handling Edible Oil through pipeline at Haldia Dock Complex (HDC), as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/66/2018-KOPT

Kolkata Port Trust

Applicant

QUORUM:

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri.Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 18th day of January 2019)

This case relates to the proposal received from Kolkata Port Trust (KOPT) seeking extension of validity for the performance norm based Penalty/ Incentive for handling Edible Oil through pipelines at Haldia Dock Complex (HDC).

2.1. It is recalled that in order to increase the pumping rate and reduce the Turn Round Time (TRT) of edible oil vessel, the KOPT had come up with a proposal in July 2017 for insertion of provisions relating to performance norm based Incentive/ Penalty for handling of Edible oil through pipelines at HDC. After following the due consultation process, this Authority vide its Order no. TAMP/59/2017-KOPT dated 14 November 2017 had approved performance norm based incentive / penalty for handling edible oil. The said Order was notified in the Gazette of India on 29 November 2017 vide Gazette No. 447. The provisions in the said Order were valid for a period of one year from 1 August 2017 to 31 July 2018.

2.2. Further, as agreed by KOPT, the KOPT was advised vide paragraph no. 8.4 of the said Order dated 14 November 2017, to review the Minimum Pumping Rate of 250 MT per hour for ships carrying Crude Palm Oil/ RBD Palm Oil and 450 MT per hour for ships carrying Crude Soya Bean/ Sunflower Oil and file a suitable proposal for the period beyond 31 July 2018, atleast 2 months prior the expiry of validity of these provisions.

3.1. In this backdrop, the KOPT vide its letter no. MTO/G/19-B/Pt.I/GMT-476 dated 30 August 2018 has filed a proposal seeking extension of validity of performance norm based Penalty / Incentive for handling Edible Oil through pipelines at HDC, as approved vide Order of November 2017. The main submissions made by KOPT are as follows:

- (i) With a view to improve the performance level of edible oil vessels as well as to increase the volume of edible oil cargo at HDC, the Board of Trustees of KOPT vide its Resolution no. R/279/HDC/ SH&CH/3/5/2017 dated 31.05.2017 had approved performance norm based Penalty/ Incentive norms for handling Edible oil through pipeline at HDC w.e.f 01.08.2017 for a period of one year and to review the same thereafter. The said norms has also been Notified by TAMP vide G.No. 447 dated 29.11.2017.
- (ii) With the introduction of the norms, the KOPT has noticed improvement in the performance of edible oil vessels as well as increase in volume of cargo as follows:

Period	Tonnage Handled	Average Productivity of Crude Palm Oil (MT/Hr)	Average Productivity of Soyabean Oil (MT/Hr)
1.8.2016 to 31.7.2017 *	2.37 MMT	160.58	286.87
1.8.2017 to 31.7.2018 **	2.40 MMT	202.21	295.38
% variation	1.35	25.92	2.61

*Period prior to implementation of performance norms based incentive / penalty

**Period after implementation of performance norm based incentive/ penalty

(iii). Since there is substantial potential for further increase of edible oil traffic at HDC, the Board of Trustees of KOPT vide its Resolution no. R/81/HDC/SH&CH/3/06/2018 dated 28.06.2018 has decided to extend the performance norm based Penalty / Incentives for handling edible oil through pipelines at HDC for a further period of 1 yearw.e.f. 01.08.2018 under the same terms and conditions. The copy of the said Board resolution is furnished by KOPT.

3.2. Accordingly, the KOPT has sought the approval of this Authority for the extension of performance norm based Penalty or Incentive for handling Edible Oil through pipelines at HDC for further period of one year w.e.f. 1 August 2018.

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the KOPT proposal dated 30 August 2018 was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 6 September 2018, seeking their comments. In response to this, some of the users organization have furnished their comments. The said comments were forwarded to KOPT as feedback information. The KOPT vide its email dated 20 September 2018 has responded.

5. A joint hearing on the case in reference was held on 1 November 2018 at the KOPT premises. At the joint hearing, the KOPT made a brief Power Point presentation of the proposal. The KOPT and the users/ user organisations have made their submissions at the joint hearing.

6. The KOPT was requested vide our letter dated 12 November 2018 to furnish some information / clarification. KOPT has responded vide its letter dated 21 December 2018. The information / clarification sought by us and reply of KOPT thereon is tabulated below.

Sl. No.	Information / Clarification sought by us	Reply of KOPT
(i).	The quantum of the incentive paid or penalty received by KOPT, on account of implementation of performance norm based incentive / penalty relating to handling of edible oil, to be furnished.	Since introduction of the scheme w.e.f. 01.08.2017 till 30.11.2018 ₹ 68,310/- has been paid by KOPT as incentive while KOPT has realized ₹ 2,81,33,615/- as penalty during the same period.
(ii).	The basis of the incentive and penalty norms proposed by KOPT, to be furnished.	The incentive as well as Penalty Norms for handling Edible Oil through Pipeline has been proposed following the guidelines of Ministry of Shipping in respect of berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016 circulated vide file No. PD-11033/73/2013 Pt dated 16.06.2016. In the said Berthing Policy, incentive as well as Penalty has been linked with the Performance Norms. The objective of the Performance linked Incentive / Disincentive Structure is to continuously drive the productivity improvement across the Ports / Customers that are exceeding the Norms. Thus, creating value for the Port in addition to allowing customers and trade to bring down the cost of logistics. The said principle has been adopted for fixing the Penalty / incentive Norms for handling liquid cargo at HDC.
(iii).	Further, during the joint hearing, the KOPT had conveyed that it can consider giving more incentives, if there is scope available. Accordingly, HDC to examine this aspect in light of the above and revise its proposal, if necessary.	Regarding payment of higher incentive, it may be stated that most of the vessels handled during the period 01.08.2016 to 31.07.2017 as well as 01.08.2017 to 31.07.2018 could not achieve the Performance Norms. Therefore, the higher incentives is not being considered at the moment.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

8. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). With a view to improve the Turnaround Time (TRT) of the edible oil vessels and thereby increase the capacity utilization of the berth, the Kolkata Port Trust (KOPT) had earlier come up with a proposal seeking approval for the Performance Norm based Incentive/ Penalty for handling Edible Oil through pipeline at Haldia Dock Complex (HDC). Accordingly, this Authority vide its Order no. TAMP/59/2017-KOPT dated 14 November 2017 had approved performance norm based incentive / penalty for handling edible oil at HDC. Vide the said Order a Minimum Pumping Rate of 250 MT per hour for ships carrying Crude Palm Oil/ RBD Palm Oil and 450 MT per hour for ships carrying Crude Soya Bean/ Sunflower Oil was fixed for a period of one year from 01 August 2017 to 31 July 2018. In this backdrop, the KOPT has come up with a proposal to extend the validity of performance norm based incentive/ penalty for handling edible oil at HDC as fixed vide the November 2017 Order for a further period of one year from 01 August 2018 to 31 July 2019. The proposal of KOPT has the approval of its Board of Trustees of KOPT.
- (ii). The submissions made by KOPT in its proposal dated 30 August 2018 alongwith the information/ clarification furnished by KOPT during the processing of the case in reference, are considered in this analysis.
- (iii). During the proceedings relating to the case which culminated into the tariff Order of November 2017, the KOPT had sought approval for implementation of the Minimum Pumping Rate along with the provisions of the incentives/ penalties for a period of one year from 01 August 2017 and had expressed its desire to review the performance norms thereafter. With the implementation of the performance norm based incentive/ penalty for handling edible oil, the port has noticed only a 25.92% increase in the average productivity of crude palm oil and a 2.61% increase in the average productivity of soyabean oil. The port has also reported that many vessels have not achieved the performance norms. As per the statistics furnished by the Port, it has paid an incentive of only ₹ 0.68 lakhs since introduction of the scheme from 01 August 2017 till 30 November 2018, whereas it has realized ₹ 281.34 lakhs as penalty during the corresponding period. Based on this position, the port in its proposal under reference has not felt it appropriate to revise upwards the prevailing Minimum Pumping Rates and has expressed its desire to extend the existing provisions relating to the performance norm based incentive/ penalty for handling edible oil at HDC for a further period of one year from 1 August 2018 to 31 July 2019.
- (iv).
 - (a). Some of the users viz., Emami Biotech Limited (EBL), Adani Wilmar Limited (AWL), JVL Oil Refinery (JVLOR), Ruchi Soya Industries Limited (RSIL) and Ruchi Infrastructure Limited (RIL) have stated that considering the number of pigging operations involved, the actual average discharge rate achieved is 180 MT per hour for Crude Palm oil/ RBD Palm Oil and 280 MT per hour for Crude sunflower oil/Crude Soyabean oil, instead of the prescribed Minimum Pumping Rate of 250 MT per hour for the ships carrying Crude Palm Oil/ RBD Palm Oil and 450 MT per hour for the ships carrying Crude Soya Bean/ Sunflower Oil. And that since the Minimum Pumping Rate cannot be achieved by the vessels, the vessels end up paying more penal charges.
 - (b). The Minimum Pumping Rate of 250 MT per hour for the ships carrying Crude Palm Oil/ RBD Palm Oil and 450 MT per hour for the ships carrying Crude Soya Bean/ Sunflower Oil as proposed by KOPT then and approved vide November 2017 Order, was based on the actual productivity achieved/ almost achieved by certain number of vessels at HDC, as reported by HDC then. This was also seen to be based on a port level meeting held by KOPT then with the relevant stakeholders.
 - (c). According to KOPT then as well as now, if the existing operational deficiencies/ constraints being faced during the discharge operation on the part of the importers/ exporters and of the vessel are fixed and appreciable action is taken by importers as well as their handling agents by deploying additional compressors, boosters, good quality pumps and nominating good quality of vessels having adequate pumping capacity etc., then the productivity levels can be easily achieved by more number of vessels.

- (v). Based on the submissions made by the KOPT and considering that the proposal of the port has the approval of its Board of Trustees and that prescription of some performance norm based incentive/ penalty will instill a discipline amongst the importers and handling agents, this Authority is inclined to extend the validity of the existing provisions of the Minimum Pumping Rate along with the provisions of the incentives/ penalties for a period of one year from 01 August 2018 and upto 31 July 2019, as requested by the Port. The port is advised to review the performance norm based incentive/ penalty for handling edible oil, while filing the proposal for the period beyond 31 July 2019. The concerned Port users are also advised to upgrade the shore infrastructure as agreed by them in the meetings held by the Port on 04 May 2017 and 18 July 2017.
- (vi). The port has quantified that it has realized an amount of ₹ 281.34 lakhs as penalty during the period of 16 months since introduction of the scheme from 01 August 2017 till 30 November 2018. If the trend of achievement / non-achievement of performance norm continues without any change, the income for the period of 8 months from December 2018 to July 2019 would work out to about ₹ 141 lakhs on pro-rata basis. In this connection, it may be recalled that in the general revision Order of KOPT passed by this Authority in November 2016, a revenue gap to the tune of about ₹ 383 crores, has been left uncovered by the Port. Thus, the additional revenue that would be generated pro-rata due to levy of penalty at the existing level would get subsumed in the revenue gap and would not lead to any undue advantage to KOPT.

9.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, the existing note (iii) under sub-section (ii) under Section 21.6 - “Performance as well as Productivity/ Incentive Norms for handling Edible Oil through pipeline at HDC” is replaced with the following note:

“(iii). The Performance and Penalty/ Incentive Norm as specified above effective from 1 August 2017 with a validity upto 31 July 2018 is further extended for a period of one year from 01 August 2018 and will remain valid upto 31 July 2019 and will be reviewed thereafter.”

9.2. The KOPT is advised to suitably incorporate the above provision in its Scale of Rates.

9.3. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority. The port is advised to review the performance norms based incentive/ penalty for handling edible oil while filing the proposal for the period beyond 31 July 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./536/18]